

सरकारी घाटे

1- राजस्व घाटा (Revenue Deficit)

↓
राजस्व खर्च - राजस्व प्राप्तियाँ

2. प्रभावी राजस्व घाटा (Effective Revenue Deficit)

राजस्व घाटा - राज्यों को दिए जाने
वाले पूंजीगत अनुदान
(Capital Grants)

संपत्ति निर्माण की शर्त पर दिये
जाने वाले अनुदान।

Note:-

वर्ष 2018-19 से भारत सरकार द्वारा राजस्व घाटे और प्रभावी राजस्व घाटे को कम करने के संवर्ध में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा रहे हैं।

(i) राष्ट्रीय संपत्तियों के रख-रखाव पर ध्यान देना।

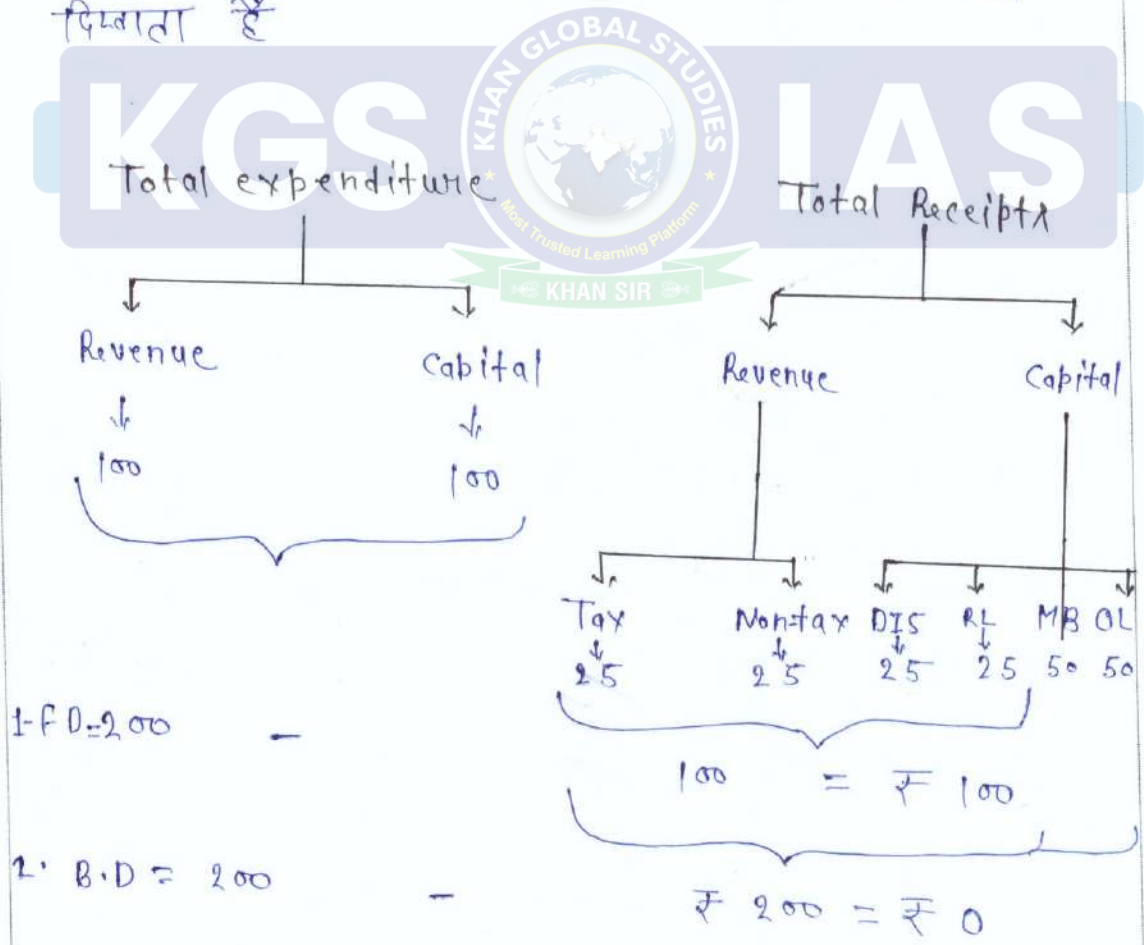
(ii) शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर आर्थिक खर्च करके मानव पूंजी निर्माण पर ध्यान देना।

3. राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit)

कुल खर्च - राजस्व प्राप्तियाँ + NDCR

इस प्रकार, राजकोषीय घाटा कुल खर्चों का कुल गैर-
 ऋणकारी प्राप्तियों पर अतिरिक्त
 (अधिक्य (Excess)) को प्रदर्शित करता है।

यह ध्यान देने योग्य है कि राजकोषीय घाटा
 सरकार की कुल उधार आवश्यकताओं को भी
 दिखाता है



भारत में राजकोषीय घाटे की अवधारणा को सुखमोय चक्रवर्ती समिति की सिफारिशों पर लागू किया गया है।

इसके लागू होने से सरकार की बजटीय प्रक्रिया में पारदर्शिता और जबाब-देही उत्पन्न हुई है इसके लागू होने से सरकार की वास्तविक राजकोषीय स्थिति का पता लग पाता है

यह ध्यान देने योग्य है कि राजकोषीय घाटे से पहले सरकार के कुल घाटे का पता लगाने के लिए बजट घाटे की अवधारणा का प्रयोग किया जाता था जिसके कारण सरकार की वास्तविक स्थिति का पता नहीं लग पाता था।

4.

बजट घाटा (Budget Deficit)

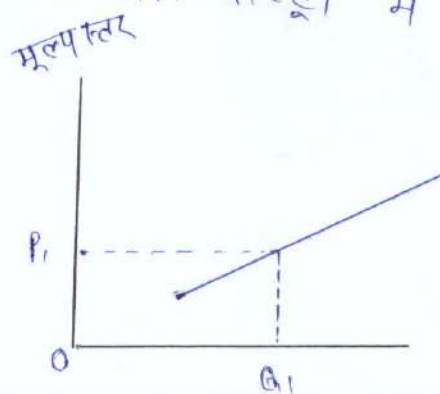
कुल खर्च - कुल प्राप्तियाँ

(ऋणकारी और गैर-ऋणकारी)

इस प्रकार, बजट घाटे को निकालते समय बाजार से उधार और अन्य देयताओं को भी प्राप्तियों मान लिया जाता है। ऐसी अवस्था में, सरकार की वास्तविक राजकोषीय स्थिति का पता नहीं लग पाता।

बजट घाटे को मौद्रिकृत बाटा भी कहा जाता है क्योंकि यदि इस घाटे का मूल्य शून्य से अधिक होता है तो इसके मूल्य के बराबर मुद्रा की मात्रा अर्थव्यवस्था में बढ़ जाती है क्योंकि इस घाटे का विलीनन करने के लिए या तो केंद्रीय बैंक से उधार लेना पड़ता है या उसके पास पड़े हुए नगद शेषों (Cash Balances) का आहरण (Withdrawal) करना पड़ता है। इन दोनों मामलों में मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी।

रुई बार इस बात का सुझाव दिया जाता है कि भारत जैसे राष्ट्र वित्तीय संसाधनों की कमी के चलते केंचे बजट घाटे के माध्यम से आर्थिक विकास के स्तर को बढ़ाने पर विचार कर सकते हैं, हालांकि इस प्रकार की राजकोषीय नीति गम्भीर आर्थिक स्थिति उत्पन्न कर सकती है ऐसा हो सकता है कि अर्थव्यवस्था too much money chasing too few goods स्थिति में फंस जाये जो अत्याधिक मुद्रास्फीति उत्पन्न कर देती है। ऐसा कि जिम्बाम्बे जैसे राष्ट्रों में देखने को मिला है



Note:-

वर्तमान में भारत में बजट घाटे को शून्य पर रखने की नीति का अनुकरण किया जा रहा है

(v) प्राथमिक घाटा (Primary Deficit)

राजकोषीय घाटा - व्याज भुगतान

